भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1653

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

रायलसीमा और नांदयाल क्षेत्र में जनजातीय समुदाय का सशक्तीकरण

†1653. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नांदयाल क्षेत्र/रायलसीमा क्षेत्र के जनजातीय बच्चों के लिए किसी नए एकलव्य विद्यालय को स्वीकृति देने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो नांदयाल क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नांदयाल क्षेत्र में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कोई धनराशि आवंटित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नांदयाल क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य स्तर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या नांदयाल क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को न्यूनतम मजदूरी अर्जित करने वाला रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नांदयाल क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनका विपणन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) तथा (ख): जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस, स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। शुरू में 288 ईएमआरएस विद्यालयों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अतंर्गत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत (अपग्रेड)

किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आज तक, 715 स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 264 जिलों के लगभग 1,33,929 छात्रों को लाभान्वित करते हुए देश भर में 476 ईएमआरएस के क्रियाशील होने की सूचना दी गई है।

रायलसीमा क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश राज्य में 28 ईएमआरएस स्वीकृत हैं, जहां अनुच्छेद 275 (1) के तहत बुचिनाइदु कंड्रिगा और ओज़िली में दो एकलव्य आदर्श (मॉडल) आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) पहले से ही क्रियाशील हैं। ये स्कूल दूरस्थ क्षेत्रों में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की पहल का हिस्सा हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच बुनियादी और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित (लागू) कर रहा है:

i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX तथा X):
ii अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर):
iii) अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (पहले शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जानी जाती थी): प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में 265 शीर्ष श्रेणी के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
iv. अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: भारत में एम.फिल या पीएचडी करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) के छात्रों को छात्रवृत्ति ।
v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) समग्र शिक्षा योजना को क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना नामांकन, प्रतिधारण और लिंग समानता के विभिन्न संकेतकों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (अजा), अजजा और अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता (सांद्रता) के आधार पर पहचाने गए विशेष ध्यान दिए जाने वाले जिलों (एसएफडी) पर ध्यान केंद्रित करती है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी छात्रावासों की स्थापना और डीए जेजीयूए के तहत जनजातीय छात्रावासों की स्थापना आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2 अक्टूबर 2024 को नांदयाल में 1 पीवीटीजी छात्रावास की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि नांदयाल जिले में अनुसूचित जनजातियों सहित वंचित समूहों की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक चलने वाले 27 कार्यात्मक केजीबीवी आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें कुल 6592 छात्राओं का नामांकन है।

(ग) तथा (घ): जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा तक बेहतर पहुँच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। आंध्र प्रदेश में नांदयाल जिले सहित पीएम जनमन के तहत दिए गए लाभों का विवरण **(21.11.2024 तक)** इसकी शुरुआत से इस प्रकार है:

मंत्रालय	**उपाय**	**स्वीकृतियां**	**वित्तीय स्वीकृतियां (करोड़ रुपए में)**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकान	32258 मकान	44.33
	संपर्क सड़कें	315.538 किमी रोड	280.53
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति	372 गांव संतृप्त	उपलब्ध नहीं है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल चिकित्सा इकाई (एमएमयू)	119 एमएमयू स्वीकृत	40.31
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	266 आंगनवाड़ी केंद्र	43.44
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास	8 छात्रावास	18.85
विद्युत मंत्रालय	आवासों (घरों) का विद्युतीकरण	25054 आवास	88.71
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	आवासों (घरों) का विद्युतीकरण	1675 आवास	8.38
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	1010 बस्तियां	94.5
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	125 एमपीसी	14.97
	वीडीवीके की स्थापना	73 वीडीवीके	3.105

संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में, कपिलेश्वरम से सिद्धेश्वरम बालापालथिप्पा जनलगुडेम होते हुए जनलगुडेम तक 7.11 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 4.40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 नई नियोजित मोबाइल चिकित्सा इकाईयों (एमएमयू) को 2 अक्टूबर 2024 को हरी झंडी दिखाई गई है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में अवसंरचनात्मक अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान के तहत प्रत्येक मंत्रालय को बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वह उसे सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। इस अभियान का उद्देश्य अभिसरण और पहुंच (आउटरीच) के माध्यम से संतृप्त करना है।

(ङ) तथा (च): जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी एजेंसी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए, 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' (पीएमजेवीएम) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) का गठन शामिल है। इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में, ट्राइफेड अपने सूचीबद्ध जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, चित्रकारी, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के तहत अपने उत्पादों के विपणन के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करता है। ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़ने के लिए मंच प्रदान करने के लिए त्योहारों, मेलों आदि का आयोजन करता है और उनमें भाग लेता है, जिससे उन्हें अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आंध्र प्रदेश में 415 वीडीवीके का गठन किया गया है।

*****